Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

मई (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- अभिनेत्री डॉ. आरुषि निशंक को मिला 'फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड' अवार्ड 3
- मिशन कर्मयोगी के तहत डॉ.एस.एस. ने ट्रेनिंग मॉड्यूल का किया शुभारंभ 3
- दृष्टिपत्र 25, संकल्प 2022 की समीक्षा 4
- उत्तराखंड कैबिनेट के महत्त्वपूर्ण निर्णय 4
- देश में पहली बार BRO ने चमोली में खोला कैफे 5
- उत्तराखंड के स्कूलों में छात्रों को मिलेंगी द्विभाषी किताबें 5
- मुख्यमंत्री ने 'साइबर एनकाउंटर्स' पुस्तक का विमोचन किया 6
- राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा तुंगनाथ मंदिर 7
- सोमनाथ मेला मासी 2023 8
- मुख्यमंत्री ने सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 के नये प्रारूप का शुभारंभ किया 8
- मुख्यमंत्री ने ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम (ए.एन.पी.आर) का शुभारंभ किया 9
- उत्तराखंड के सभी गाँव होंगे प्लास्टिक कचरे से मुक्त 10
- मुख्यमंत्री ने किया हाथीबड़कला में श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ 10
- मुख्यमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र से जुडे उद्यमियों एवं व्यापारियों को प्रदान किया 'हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड' 11
- राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 'होम्योकॉन 2023' का शुभारंभ 11
- एकल महिलाओं को स्वरोज़गार के लिये परियोजना लागत पर 75% सब्सिडी देगी राज्य सरकार 12
- पूरे राज्य का जीआईए मैप किया जाएगा तैयार 12
- ब्रांडेड उत्पादों के बिलों को भी 'बिल लाओ इनाम पाओ' योजना में किया जाएगा शामिल 13
- वन्यजीवों से फसलों को बचाने के लिये अब होगी बॉयो-फेंसिंग 13
- बाबा केदार के धाम में स्थापित होगा 60 क्विंटल वजनी काँसे का भव्य ऊँ 14
- राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को वापस लेगी सरकार 15
- 'पैच रिपोर्टिंग एप' 15
- प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर 16
- जमरानी बांध विस्थापित परिवारों के लिये 300 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी 17
- स्थानीय समुदाय पर खर्च होगी ईको टूरिज्म की 90% कमाई 17
- प्रदेश को जल्द मिलेगी साइबर फॉरेंसिक लैब 18
- अमर उजाला प्रथमा सम्मान 18
- पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड और गोवा बनेंगे सहयोगी 19
- दून जू में शुरू होगी टाइगर सफारी 20
- प्रधानमंत्री ने देहरादून से दिल्ली के बीच 'वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन' की पहली यात्रा का शुभारंभ झंडी दिखाकर किया 21
- गंगोत्री में 5जी की दो लाखवीं साइट लॉन्च 22
- उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2023 को मिली मंजूरी 23
- वाइब्रेंट विलेज के निवासियों को दो घर देने की तैयारी 24
- मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण निधि (कॉर्प्स फंड) 24
- प्रदेश की 1114 गाँवों में फाइबर टू होम कनेक्शन से फ्री वाईफाई 25

नोट :

उत्तराखंड

अभिनेत्री डॉ. आरुषि निशंक को मिला 'फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड' अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

29 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड की प्रसिद्ध अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और सामाजिक कार्यकर्त्ता डॉ. आरुषी निशंक को दुबई में ग्लोबल इंस्पिरेशनल अवाड्र्स और फैशन फेस्टिवल में शेख याकूब अल अली और एचई आरेफा अल फलाही की ओर से 'फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड' के रूप में सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह अवार्ड आरुषी निशंक को बतौर एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर के रूप में बॉलीवुड में उनके बेहतरीन काम के लिये दिया गया।
- उल्लेखनीय है कि आरुषि निशंक का जन्म उत्तराखंड के कोटद्वार में हुआ है। आरुषि के पिता डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार क्षेत्र से सांसद हैं और वह पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं।
- टी-सीरीज और जी-म्यूजिक के तीन म्यूजिक वीडियो का हिस्सा बनकर प्रसिद्धि पाने वाली आरुषी फिल्म 'तारिणी' में नज़र आएंगी।
- आरुषी निशंक अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस-हिमश्री फिल्म्स चलाती हैं तथा डिज्नी+हॉटस्टार के साथ एक शो का निर्माण कर रही हैं।

मिशन कर्मयोगी के तहत डॉ.एस.एस. ने ट्रेनिंग मॉड्यूल का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

1 मई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में मिशन कर्मयोगी के तहत राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी द्वारा तैयार ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव ने सभी विभागों को शीघ्र iGOT पोर्टल पर ऑनबोर्ड किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि iGOT पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने के लिये सभी विभागों के नोडल अधिकारी शीघ्र नामित किये जाएँ।
- महानिदेशक डॉ. आर. एस. टोलिया व उत्तराखंड प्रशासन अकादमी बी. पी. पांडेय के अनुसार iGOT पोर्टल पर अभी तक 72 में से 36 विभाग ऑनबोर्ड हो गए हैं। इस ऑनलाइन पोर्टल पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध रहेगी, जिसे विभागीय कर्मी सरकारी ईमेल आईडी के माध्यम से ईलर्निंग सामग्री प्राप्त कर सकेंगे।
- जिन विभागों के पास पहले से अपनी प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध हैं, वे इस पोर्टल पर अपलोड की जा सकेगी, ताकि सभी कर्मियों को आसानी से प्राप्त हो सके। पोर्टल पर अब तक 120 प्रशिक्षण मॉड्यूल अपलोड किये जा चुके हैं, अगले माह तक जिनकी संख्या लगभग 200 हो जाएगी।

दृष्टिपत्र 25, संकल्प 2022 की समीक्षा

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में सचिवालय में सरकार के ''दृष्टिपत्र 25, संकल्प 2022'' की समीक्षा की गई।

प्रमुख बिंदु

- समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने जनरल बिपिन सिंह रावत पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी योजना के तहत प्रदेश के पूर्व सैनिक इस योजना का लाभ अधिक से अधिक उठा पाएँ, इसके लिये प्रदेश का डाटा एकत्रित किये जाने के निर्देश दिये। साथ ही इस परियोजना का प्रतिदिन मॉनिटरिंग किये जाने के भी निर्देश दिये।
- उन्होंने मानसखंड सर्किट तक पहुंच आसान बनाने के लिये टनकपुर, रामनगर और हल्द्वानी से मानसखंड सर्किट के लिये सड़कों के विकास पर फोकस किये जाने के निर्देश दिये।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूती प्रदान करने के लिये उनके द्वारा बनाए उत्पादों को बाज़ार उपलब्ध कराया जाए। मार्केटिंग के लिये ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाए। साथ ही राज्य में जन औषधि केंद्रों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाए जाने के निर्देश दिये।
- प्रदेशभर में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये अधिक से अधिक ईको टूरिज्म स्थल चिह्नित कर विकसित किये जाने के निर्देश दिये और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किये जाने की दिशा में अधिक से अधिक प्रस्ताव लाने के निर्देश दिये।
- मुख्य सचिव ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाए जाने में तेजी लाते हुए योजना को शीघ्र धरातल पर उतारे जाने के निर्देश दिये एवं उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण के साथ ही हॉस्टल उपलब्ध कराए जाने पर फोकस किये जाने के निर्देश दिये।

उत्तराखंड कैबिनेट के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

3 मई, 2023 को उत्तराखंड के कैबिनेट ने नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु (स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड) को मंजूरी देने के साथ कई अन्य महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार का मार्च 2023 में एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोज़गार योजना की घोषणा की थी।
- अब इस योजना के तहत एएनएम, जीएनएम पास युवाओं को जर्मनी, जापान आदि देशों में नर्सिंग, बुजुर्गों की देखभाल, हॉस्पिटैलिटी के लिये रोज़गार दिलाया जाएगा। इसके लिये 11 संस्थाओं से प्रस्ताव मिल चुके हैं। चुने हुए युवाओं को विदेशी भाषा सीखने के लिये होने वाले कुल खर्च में से 20 प्रतिशत सरकार वहन करेगी।

नोट :

- इसके अलावा काई युवा अगर प्रशिक्षण, वीजा व हवाई टिकट के खर्च के लिये लोन लेगा तो 1 लाख तक लोन के ब्याज का 75 प्रतिशत खर्च भी सरकार वहन करेगी।
- सेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में काम करेगा। इसके उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री या मुख्यमंत्री की ओर से नामित मंत्री होंगे। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर बाहरी विशेषज्ञ रखा जाएगा। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर अपर सचिव स्तर का अधिकारी होगा।
- इसमें प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए केंद्र से मिलेंगे। इसमें 3 सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस और सेंटर फॉर एविडेंस बेस्ड प्लानिंग तथा 6 सलाहकार आर्थिकी एवं रोजगार, सामाजिक अवसंरचना, पब्लिक पॉलिसी एवं सुशासन, शहरी एवं अर्द्धशहरी विकास, सांख्यिकी एंव डेटा, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने के लिये बाहर से विशेषज्ञ लिये जाएंगे।
- कैबिनेट निर्णय में यह भी तय किया गया है कि किसी भी स्कूल, अस्पताल आदि के लिये ज़मीन की तलाश हेतु हर ज़िले में डीएम की अध्यक्षता में साइट सेलेक्शन कमेटी गठित की जाएगी।
- इस अवसर पर प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य पशुधन मिशन को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है।
- इसके तहत 125 विश्वस्तरीय वेटरेनरी हॉस्पिटल बनेंगे तो 575 पशु चिकित्सालयों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। घोड़ा-खच्चर से भी उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। अब इसमें घोड़ा-खच्चर की खरीद भी शामिल की गई है।
- इसके तहत दुधारू पशु, भेड़-बकरी, मुर्गी के साथ ही व्यवसाय के लिये घोड़ा खच्चर खरीदने पर भी लोन के ब्याज में 9 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।
- कैबिनेट ने उत्तराखंड चारा नीति 2023 को मंजूरी दी है। इसके तहत हरा और सूखा चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये 66 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है।
- यह नीति पाँच साल के लिये होगी। इसके तहत 10 भूसा भंडारण गृह बनाए जाएंगे।
- प्राकृतिक आपदा होने पर प्रदेश में चारे की निर्बाध आपूर्ति के लिये कारपस फंड बनाया जाएगा।
- अभी तक प्रदेश में पिरूल एकत्र करने वालों को सरकार दो रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से भुगतान करती है। इसमें बढ़ोतरी कर इसके तहत अब तीन रुपए प्रति किलो का भुगतान होगा।
- कैबिनेट ने प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ के गठन को मंजूरी दी है।
- यह प्रकोष्ठ जहाँ मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारणों को तलाश कर इसके निवारण को सुझाव सरकार को देगा, वहीं मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटना पर मुआवज़ा भी तत्काल उपलब्ध कराएगा। इसके लिये दो करोड़ का कारपस फंड बनाया जाएगा।

देश में पहली बार BRO ने चमोली में खोला कैफे

चर्चा में क्यों ?

7 मई, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के 64वें स्थापना दिवस पर रक्षा राज्यमंत्री अजय भटे ने उत्तराखंड में बदरीनाथ हाईवे पर चमोली ज़िले के पांडुकेश्वर में देश में बीआरओ के पहले कैफे का वर्चुअली उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- बीआरओ की ओर से पांडुकेश्वर में खोला गया कैफे संगठन का पहला कैफे है। इसमें बदरीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिये खाने की बेहतरीन सुविधा दी जाएगी।
- बीआरओ की इस नई पहल से तीर्थयात्रा पर आने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।
- देश में जहाँ भी बीआरओ की सड़कें हैं, उनके किनारे 75 जगहों पर कैफे खोले जाएंगे।

उत्तराखंड के स्कूलों में छात्रों को मिलेंगी द्विभाषी किताबें

चर्चा में क्यों ?

6 मई, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विद्यालयी शिक्षा की समीक्षा के

नोट :

दौरान बताया कि अगले सत्र से प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को विज्ञान, गणित और नागरिकशास्त्र की द्विभाषी किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीईआरटी की ऐसी प्रत्येक विषय की पुस्तक में बाँया पेज हिन्दी और दाहिना पेज अंग्रेज़ी भाषा में होगा। इससे हिन्दी और अंग्रेज़ी माध्यम के बच्चों के लिये पढ़ाई करना और सहज हो सकेगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन ज़िलों में विद्यालयी शिक्षा के तहत विद्यार्थी ड्रॉपआउट हो रहे हैं, इनके कारणों का अध्ययन किया जाए तथा ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करने के लिये हरसंभव प्रयास किये जाएँ और सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के प्रयास किये जाएँ।
- पीएमश्री के तहत राज्य के चयनित 142 स्कूलों के लिये सभी आवश्यक ज़रूरी सुविधाएँ जुटाई जाएंगी। स्कूली शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- पॉलिटेक्निक कॉलेजों एवं आईटीआई में समय की मांग के आधार पर कोर्स करवाए जाएंगे। इसके लिये औद्योगिक संस्थानों से निरंतर आपसी समन्वय बनाया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थियों को उचित प्लेसमेंट मिल जाए।
- पॉलिटेक्निक कॉलेजों एवं आईटीआई के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए यह तय किया जाए कि इनमें दक्ष मानव संसाधन के साथ आवश्यक उपकरण भी हों। जिस ट्रेड में कार्य के लिये मांग बढ़ी है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। पॉलिटेक्निक कॉलेजों और आईटीआई का अपग्रेडेशन भी चरणबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिये।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा उच्च शिक्षा के साथ व्यावसायिक कोर्स को बढ़ावा देने पर भी कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने 'साइबर एनकाउंटर्स' पुस्तक का विमोचन किया

चर्चा में क्यों ?

7 मई, 2023 को उतराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड स्थित सेंट जोसेफ अकेडमी, देहरादून में 'साइबर एनकाउंटर्स' पुस्तक के हिन्दी संस्करण का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- यह पुस्तक डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार एवं पूर्व डी.आर.डी.ओ वैज्ञानिक ओ.पी. मनोचा द्वारा लिखी गई है।
- डीजीपी अशोक कुमार एवं ओ.पी मनोचा ने साइबर अपराधों का विश्लेषण करती व सत्य घटनाओं पर आधारित यह पुस्तक लिखी है, इससे साइबर अपराधों से बचने में पाठकों को बहुत मदद मिलेगी। इस पुस्तक में जहाँ एक ओर सच्ची घटनाओं का जिक्र करते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी ओर पुस्तक मनोरंजक भी है। पुस्तक का एक-एक पृष्ठ लोगों को साइबर क्राइम से बचाव के लिये प्रेरित करने का कार्य करेगा।
- साइबर क्राइम वर्तमान टेक्नोलॉजी के युग की सबसे बड़ी चुनौती है और प्रदेश के डीजीपी द्वारा इस चुनौती के संबंध में जनता को जागरूक करना इस पुस्तक की प्रासंगिकता को और भी अधिक बढ़ा देता है।
- उल्लेखनीय है कि इस पुस्तक के लेखक डीजीपी अशोक कुमार उत्तराखंड कैडर के वर्ष 1989 के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हैं।
- 30 नवंबर, 2020 को वे उत्तराखंड के 11वें डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) बने। अपने लगभग तीन दशक के सेवाकाल में अविभाजित उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड पुलिस, आईटीबीपी और बीएसएफ के महत्त्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे हैं। बीते वर्षों में उन्होंने कई विषयों पर पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें उनकी 'खाकी में इंसान' पुस्तक बेहद प्रसिद्ध रही है।
- अशोक कुमार का जन्म 20 नवंबर 1964 को हरियाणा के पानीपत ज़िले के कुराना गांव में हुआ था। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक और एमटेक की शिक्षा प्राप्त की थी।

नोट :

- डीजीपी अशोक कुमार को वर्ष 2001 में कोसोवो में उत्कृष्ट कार्य के लिये यूनए मिशन पदक मिला था। उन्हें वर्ष 2006 में दीर्घ एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया।
- ओ.पी मनोचा डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं। ओ. पी. मनोचा भौतिकी (इलेक्ट्रॉनिक्स) में पोस्ट ग्रैजुएट हैं और उन्हें रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान विंग डी.आर.डी.ओ. में काम करने का 35 साल का अनुभव है, जहाँ उन्होंने विभिन्न रक्षा परियोजनाओं को धरातल पर उतारा।
- विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं तथा सम्मेलनों में उनकी छह कृतियाँ प्रकाशित हैं, जिनमें डिफेंस साइंस जर्नल, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इमेज इनफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांसेज इन कंप्यूटर साइंस की कार्रवाइयाँ शामिल हैं।
- वे इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लाइफ फेलो हैं और कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग के आजीवन सदस्य हैं। वे IETE, देहरादून चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष हैं। वे वर्ष 2018 में डी.आर. डी.ओ. से सेवानिवृत्त हुए।

राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा तुंगनाथ मंदिर

चर्चा में क्यों ?

6 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के पुरातत्त्व विभाग के प्रभारी अधिकारी देवराज सिंह रौतेला ने बताया कि पंचकेदारों में से तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि राज्य के रुद्रप्रयाग ज़िले में तुंगनाथ मंदिर एशिया में समुद्रतल से सबसे ऊँचाई (12800 फीट) पर स्थापित शिवालय है। रुद्रप्रयाग ज़िला मुख्यालय से तुंगनाथ मंदिर की दूरी 70 किमी. है। चोपता से चार किमी. पैदल चढ़ाई कर मंदिर तक पहुँचते हैं।
- गौरतलब है कि प्राचीन मंदिर तुंगनाथ को राष्ट्रीय महत्त्व स्मारक घोषित करने के लिये केंद्र सरकार ने 27 मार्च, 2023 को अधिसूचना जारी की है।

तृतीय केदार तुंगनाथ

नोट :

सोमनाथ मेला मासी 2023

चर्चा में क्यों ?

8 मई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक सोमनाथ मेला मासी 2023 में प्रतिभाग करते हुए सोमनाथ मेले को 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि सोमनाथ मासी मेले का आयोजन कुमाऊँ मंडल के अल्मोड़ा जनपद की तहसील रानीखेत के मासी नामक गाँव में रामगंगा नदी के उस पार स्थित सोमेश्वर महादेव के मंदिर के सामने नदी तट पर होता है।
- इसका प्रारंभ वैसाख के अंतिम रविवार को होता है तथा पहली सत्र के मेले को 'सल्टिया मेला' कहा जाता है। इसका मुख्य आकर्षण वैसाख के अंतिम सोमवार को सोमनाथ के मंदिर के सामने रामगंगा के इस ओर के तट पर नदी में पत्थर फेंककर पानी उछालने की प्रतियोगिता होती है।
- यह प्रतियोगिता पालीपछाऊ के दो धड़ों मासीवाल तथा कनूडिया के बीच होती है। एतदर्थ दोनों धड़ों के लोग अपने-अपने निशानों (ध्वजों) व ढोल-नगाड़ा के साथ आकर रामगंगा के किनारे एक नियत स्थान पर ऽड़े हो जाते हैं तथा दोनों धड़ों के प्रधानों के द्वारा नियत समय पर प्रतियोगिता प्रारंभ करने के लिये उनके संकेतों की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही उनकी ओर से झंडी या सीटी का संकेत मिलता है वैसे ही दोनों धड़ों के लोग हाथों से बड़े-बड़े पत्थर नदी में फैंकते और उछाले गए जल को अपने उपर लेने का प्रयास करते हैं। यह जल पवित्र माना जाता है।

मुख्यमंत्री ने सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 के नये प्रारूप का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

9 मई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 के नये प्रारूप का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- सीएम हेल्प लाईन 1905 के नये वर्जन में 1905 डायल करने के अलावा वेब पोर्टल, मोबाइल एप एवं ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग फीचर की सुविधा भी दी गई है।
- अब 24 घंटे सीएम हेल्पलाइन 1905 पर मदद लिये जाने के साथ शिकायत भी दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाइन 1905 की विभागों द्वारा माह में दो बार समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में इसकी स्वयं समीक्षा करेंगे।
- मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाइन 1905 से लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जन समस्याओं एवं शिकायतों के निस्तारण के लिये बनाए गए इस हेल्पलाईन का लाभ आमजन को मिले।
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए जन समस्याओं का उनके स्तर पर ही समाधान हो जाए। तहसील स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है, वे अनावश्यक ज़िलाधिकारी तक न आए और जिन समस्याओं का समाधान जनपद स्तर पर होना है वे शासन स्तर तक न आएं। जिस स्तर पर समस्याओं का समाधान होना है, यदि नहीं हो रहा है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाए।
- भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 को और अधिक सशक्त बनाया जाए। तहसील दिवसों का नियमित आयोजन किया जाए। जनपद स्तर पर भी ज़िलाधिकारी प्रतिमाह जनसुनवाई करें। प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को तहसील जन समर्पण दिवस का आयोजन किया जाए एवं चौथे मंगलवार को जनपद में ज़िलाधिकारी जन समर्पण दिवस लगाकर जन समस्याओं का समाधान करें।
- सभी जन समस्याओं एवं जन शिकायतों को ऑनलाईन रजिस्टर किया जाए। जिन लोगों की समस्याओं का समाधान तहसील एवं जनपद स्तर पर नहीं हो पाएगा, उन समस्याओं को ही मुख्यमंत्री कार्यालय को संदर्भित किया जाएगा।

नोट :

मुख्यमंत्री ने ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम (ए.एन.पी.आर) का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

9 मई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से परिवहन विभाग द्वारा तैयार किये गए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम (ए.एन.पी.आर) का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम से प्रदेश के प्रमुख मार्गों में यातायात के नियमों के अनुपालन एवं कर अपवंचन संबंधी प्रकरणों की ऑनलाईन मॉनिटरिंग की सुविधा मिलेगी।
- ए.एन.पी.आर कैमरे लगने से जीएसटी एवं अन्य विभागों को भी मदद मिलेगी व कर चोरी पर रोकथाम भी इससे संभव होगा। इससे चेक पोस्टों पर जाम से मुक्ति मिलेगी और आवागमन भी सरल होगा। इसके साथ ही इस व्यवस्था के प्रारंभ होने से वाहन दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी।
- सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग किये जाने की व्यवस्था की गई है।
- उत्तराखंड में राज्य की सीमा पर स्थापित सभी चैक पोस्टों को समाप्त कर दिया गया है। राज्य में इलैक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू करने हेतु प्रथम चरण में राज्य की सीमा पर ए.एन.पी.आर. स्थापित करने की योजना बनाई गई जिसके लिये राज्य सड़क सुरक्षा कोष से 4.61 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है।
- उत्तराखंड परिवहन सचिव ने जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत ए.एन.पी.आर. पोर्टल से प्राप्त डाटा को जीएसटी विभाग को उपलब्ध कराने हेतु इंटीग्रेशन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, जबकि अन्य विभागों-खनन, आबकारी, पर्यटन, शहरी विकास, वन विभाग तथा पुलिस के साथ इंटीग्रेशन किया जाना भी प्रस्तावित है ताकि एक ही माध्यम से प्राप्त डाटा का सभी संबंधित विभागों द्वारा उपयोग किया जा सके।
- इस व्यवस्था को पूर्णत: आटोमेटेड बनाया गया है जिसके लिये ए.एन.पी.आर. कैमरे के लिये तैयार सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन वाहन पोर्टल एवं ई-चालान पोर्टल से किया गया है। इससे वाहन के नंबर प्लेट के आधार पर चालान स्वत: जेनरेट हो सकेंगे, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा।

नोट :

उत्तराखंड के सभी गाँव होंगे प्लास्टिक कचरे से मुक्त

चर्चा में क्यों ?

11 मई, 2023 को उत्तराखंड के ग्राम्य विकास आयुक्त एवं पंचायत निदेशक आनंद स्वरूप ने बताया कि प्रदेश की 7791 ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा, जिसकी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायतों की मदद से हर घर से प्लास्टिक कूड़ा उठाने से लेकर उसके निपटारे तक की कार्रवाई की जाएगी। इस काम के लिये केंद्र सरकार की ओर से 15वें वित्त आयोग में धन की व्यवस्था की गई है।
- गौरतलब है कि प्रदेश में 'उत्तराखंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट' -2013 लागू है। गाँव-गाँव में प्लास्टिक पहुँच चुका है, लेकिन एक्ट में दी गई व्यवस्थाओं के तहत गाँवों में इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा था।
- नई योजना के तहत प्रदेश के 70 प्रतिशत गाँवों में काफी हद तक काम शुरू भी हो चुका है।
- इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर घर-घर से प्लास्टिक कचरे का एकत्रीकरण कर उसे रोड हेड तक पहुँचाया जाएगा। इसके बाद क्षेत्र पंचायत (ब्लॉक) स्तर पर कूड़ा गाड़ियों के माध्यम से इस कचरे को कांपैक्टर तक पहुँचाया जाएगा। अगला काम ज़िला पंचायतों का होगा, जो कांपैक्ट किये गए कूड़े को निस्तारण के लिये प्लास्टिक वेस्ट प्लांट तक पहुँचाएंगी। यह पूरी श्रृंखला एक क्लस्टर के तहत काम करेगी।
- इस योजना के तहत प्लास्टिक कचरे को उठाकर कांपैक्टर तक पहुँचाने के लिये प्रदेश के 95 ब्लॉकों को 95 गाड़ियाँ (पिकअप वाहन) उपलब्ध कराई जाएंगी।
- इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 95 ब्लाको में कांपैक्टर लगाए जाने हैं। जबकि अभी तक 69 ब्लॉक में ये लगाए जा चुके हैं।
- इसके अलावा हरिद्वार में बंद पड़े रिसाइकिलिंग प्लांट को भी पुन: शुरू कर दिया गया है, जहाँ कांपैक्ट किये गए प्लास्टिक कूड़े का निस्तारण किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में सामाजिक कार्यकर्त्ता जितेंद्र यादव की एक जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को गाँवों को प्लास्टिक से मुक्त बनाने के निर्देश दिये थे। इसके साथ ही इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराने के भी निर्देश दिये थे।

मुख्यमंत्री ने किया हाथीबड़कला में श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

13 मई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून ज़िले के हाथीबड़कला स्थित सर्वे स्टेडियम में श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- चार दिन तक चलने वाले श्री अन्न महोत्सव में प्रदेशभर से हज़ारों किसान प्रतिभाग कर रहे हैं।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मिलेट्स पर आधारित विभिन्न स्टालों का निरीक्षण किया एवं कृषि विभाग उत्तराखंड की पौष्टिक फसलों पर आधारित पुस्तक 'स्वाद के साथ स्वास्थ्य' का विमोचन किया।
- यह आयोजन 'श्री अन्न'को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह के आयोजनों से न केवल मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे किसानों को भी मोटे अनाजों से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त होंगी।
- उल्लेखनीय है कि देश में वर्ष 2023 को 'मिलेट्स ईयर'के रूप में मनाया जा रहा है तथा भारत के प्रस्ताव पर ही 'संयुक्त राष्ट्र संघ'ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है।
- उत्तराखंड राज्य सरकार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में मिलेट की खेती को प्रोत्साहित करने के लिये सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करने और रोज़गार उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है।

नोट :

- राज्य के पर्वतीय ज़िलों के कृषकों से मंडवा, झिंगोरा, चौलाई जैसे मोटे अनाजों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है साथ ही, किसानों को इसका ऑनलाइन भुगतान भी किया जा रहा है। इससे न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि मिलेट उत्पादों के उत्पादन हेतु किसान प्रोत्साहित भी हो रहे हैं।
- प्रदेश में सरकार द्वारा मिलेट फसलों को प्रोत्साहन तथा आम जनमानस के भोजन में सम्मिलित करने हेतु लगभग 73 करोड़ रुपए की धनराशि स्टेट मिलेट मिशन को दी गई है।
- जैविक कृषि के साथ-साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के 11 जनपदों में इस वर्ष से आरंभ किया जा रहा है। इसके लिये भारत सरकार द्वारा 6400 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 796 लाख के कृषि मिशन कार्यक्रम के संचालन की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है।
- जैविक खेती के क्षेत्र में भी राज्य में अच्छा कार्य करने के लिये उत्तराखंड को लगातार दो साल प्रथम पुरस्कार मिला है।

मुख्यमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र से जुडे उद्यमियों एवं व्यापारियों को प्रदान किया 'हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड'

चर्चा में क्यों ?

13 मई, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक न्यूज चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों एवं व्यापारियों को 'हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड'प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न पर्यटन व्यवसायियों के साथ मीडिया से बेहतर समन्वय तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार में योगदान के लिये महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी तथा वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिये सुशांत पटनायक को भी सम्मानित किया।
- विदित है कि पर्यटन की दृष्टि से पूरा उत्तराखंड ही एक डेस्टिनेशन है तथा राज्य को विभिन्न सर्किटों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर्यटन के साथ एडवेंचर टूरिज्म एवं अन्य पर्यटन गतिविधियों में भी प्रदेश में अनेक संभावनाएँ हैं।
- राज्य के नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटन, उद्योग एवं व्यापार की यहाँ अपार संभावनाएँ हैं। हेमकुंट साहिब एवं गौरीकुंड से केदारनाथ तक के रोपवे का शिलान्यास कर दिया गया है इससे आने वाले समय में यात्रा और सुगम होगी। ऑल वेदर रोड के निर्माण तथा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाईन निर्माण से पहले के मुकाबले यात्री बेहद कम समय में ऋषिकेश से चार धाम पहुँचेंगे।

राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 'होम्योकॉन 2023' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

14 मई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 'होम्योकॉन 2023' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने होम्योपैथिक पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लॉच किया तथा होम्योपैथी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित भी किया।
- गौरतलब है कि भारत में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में पृथक् से आयुष मंत्रालय का गठन किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा होम्योपैथी को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रचलित चिकित्सा पद्धति माना गया है।
- मुख्यमंत्री ने होम्योपैथी के जन्मदाता सैमुअल क्रिश्चियन हैनिमैन का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने होम्योपैथी के रूप में एक ऐसी उपचार पद्धति विकसित की, जो अत्यंत कारगर होने के साथ-साथ किफायती भी है।

नोट :

- उत्तराखंड राज्य सरकार देवभूमि को एक महत्त्वपूर्ण आयुष प्रदेश के रूप में स्थापित करने हेतु कृत-संकल्पित है। उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य में आयुष और विशेष रूप से किफायती और कारगर होने के कारण होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की महत्ता और बढ़ जाती है।

एकल महिलाओं को स्वरोज़गार के लिये परियोजना लागत पर 75% सब्सिडी देगी राज्य सरकार

चर्चा में क्यों ?

15 मई, 2023 को उत्तराखंड की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मीडिया को बताया कि उत्तराखंड में एकल महिलाओं को स्वरोज़गार के लिये राज्य सरकार परियोजना लागत पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी।

प्रमुख बिंदु

- विभागीय मंत्री ने बताया कि 50 हज़ार से दो लाख रुपए तक की परियोजना पर यह सब्सिडी मिलेगी, जबकि, 25 प्रतिशत धनराशि बिना गारंटर के ऋण के रूप में दी जाएगी।
- विभागीय मंत्री ने बताया कि एकल महिलाओं के स्वरोज़गार के लिये निदेशालय स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यह न्याय, वित्त और कार्मिक विभाग की मंजूरी के बाद अगली कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
- विभागीय मंत्री ने कहा कि पहले साल में 500 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। राज्य में करीब डेढ़ लाख एकल महिलाएँ हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी कल्याण कोष से कार्यकर्त्ताओं को मिलने वाली 30 हज़ार रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए किया जाएगा। दोनों प्रस्तावों को अगली कैबिनेट में लाया जाएगा।
- मंत्री ने बताया कि राज्य में चार लाख एकल महिलाएँ हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये 'एकल महिला स्वरोज़गार' के नाम से जो योजना शुरू की जानी है, उस दायरे में करीब डेढ़ लाख महिलाएँ आएंगी।
- ये महिलाएँ पशुपालन, ब्यूटी पार्लर, चाय की दुकान आदि कोई भी स्वरोज़गार से जुड़ा काम कर सकेंगी।
- योजना का लाभ पाने के लिये महिला की उम्र 22 से 45 वर्ष और सालाना आय 72 हज़ार रुपए से कम होनी चाहिये।
- एकल महिलाओं में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अविवाहित महिलाओं के साथ ही किन्नर भी इस योजना के लिये पात्र होंगे।
- मंत्री ने बैठक में महालक्ष्मी किट का दायरा बढ़ाते हुए बालक के जन्म पर भी किट दिये जाने के लिये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये।

पूरे राज्य का जीआईए मैप किया जाएगा तैयार

चर्चा में क्यों ?

14 मई, 2023 को उत्तराखंड राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव, चंद्रेश यादव ने मीडिया को बताया कि पहली बार आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए प्रदेश की संपूर्ण भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश का जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) से नक्शा तैयार किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार की ओर से इसके लिये 150 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड राजस्व परिषद को इस काम के लिये नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- उत्तराखंड राजस्व परिषद डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के तहत राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि का सर्वेक्षण करेगी। इसके साथ ही सभी सरकारी विभागों की भूमि का ब्योरा भी जुटाया जाएगा।
- डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम के तहत प्रदेश की संपूर्ण भूमि के सर्वेक्षण का काम करीब दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव की ओर से आदेश निर्गत होने के बाद आरएफटी टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- सर्वे का काम एरियल लिडार (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) तकनीक से किया जाएगा। यह सर्वे की एरियल मैपिंग तकनीक है, जो धरती की सतह से कैलिब्रेटेड लेजर रिटर्न का उपयोग करती है और ऑन-बोर्ड पोजिशनल और आईएमयू सेंसर से लैस जीपीएस-निगरानी वाले विमान के माध्यम से पूरी की जाती है।

नोट :

- विदित है कि प्रदेश का अधिकांश भूभाग (नौ ज़िले) पर्वतीय होने के कारण तमाम जमीनें गोल खातों के विवाद में उलझी हैं। सरकार कई विकास योजनाओं को भूमि की अनुपलब्धता के कारण शुरू नहीं कर पा रही है। वहीं, कई विभागों के पास अपनी ही उपलब्ध भूमि का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।
- इन सब समस्याओं से पार पाने के लिये सरकार ने अब संपूर्ण भूमि का सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इसके लिये मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु की अध्यक्षता में शासी निकाय का गठन किया गया है, जिसमें सभी विभागों के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव व विभागाध्यक्षों को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।
- प्रदेश में संपूर्ण भूमि का सर्वे होने और जीआईएस मैप तैयार हो जाने के बाद भूमि विवाद से संबंधी मसलों को हल करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही प्लानिंग के स्तर पर सरकार को निर्णय लेने में आसानी होगी। हर भूमि का भू आधार नंबर (यूएलआईपीएन) तैयार होगा।

ब्रांडेड उत्पादों के बिलों को भी 'बिल लाओ इनाम पाओ' योजना में किया जाएगा शामिल

चर्चा में क्यों ?

15 मई, 2023 को उत्तराखंड राज्य कर आयुक्त इकबाल अहमद ने बताया कि 'बिल लाओ इनाम पाओ' योजना को नवंबर 2023 तक बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार ने नॉन ब्रांडेड बिलों की शर्त को खत्म कर दिया है। अब ब्रांडेड उत्पादों के बिलों को भी योजना में शामिल किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि ग्राहकों को जीएसटी बिल लेने के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'बिल लाओ इनाम पाओ' योजना को एक सितंबर 2022 में शुरू की गई थी।
- अभी तक योजना में नॉन ब्रांडेड कपड़े, मिठाइयाँ, रेस्टोरेंट, ड्राई फ्रूट, ब्यूटीपार्लर, लॉन्ड्री सेवाओं व उत्पादों के जीएसटी बिल शामिल किये जा रहे थे, लेकिन अब ब्रांडेड समेत सभी सामान की खरीद के जीएसटी बिलों से योजना में इनाम पाने का मौका मिलेगा। योजना का मेगा लकी ड्रॉ नवंबर 2023 में निकाला जाएगा।
- राज्य कर आयुक्त इकबाल अहमद ने बताया कि यदि उपभोक्ता ब्रांडेड कंपनी के सामान के अलावा घर की ज़रूरत के सामान भी खरीदता है तो जीएसटी बिल को BLIP एप पर अपलोड कर सकता है। उसके बाद लकी ड्रॉ से हर महीने 1500 विजेताओं को स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच और इयरफोन इनाम में दिये जाएंगे।
- एक सितंबर 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक अपलोड किये बिलों पर मेगा लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे, जिनमें विजेताओं को कार, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी समेत कई आकर्षक इनाम दिये जाएंगे।
- ऑनलाइन खरीद से प्राप्त जीएसटी बिलों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। सीधे विक्रेता से वस्तुओं, सेवाओं के बिलों को योजना में शामिल होंगे। इन बिलों को BLIP एप पर अपलोड करना होगा। अपलोड किये गए प्रत्येक अपलोड बिल पर उपभोक्ताओं को प्वाइंट दिये जाएंगे, जो पुरस्कार, कैश बैक, डिस्काउंट कूपन के रूप में होंगे।
- योजना में ऐसे जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा, जिनके प्रतिष्ठान से सर्वाधिक बिल अपलोड किये जाएंगे।

वन्यजीवों से फसलों को बचाने के लिये अब होगी बॉयो-फेंसिंग

चर्चा में क्यों ?

16 मई, 2023 को उत्तराखंड वन विभाग के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डॉ. समीर सिन्हा ने बताया कि राज्य में वन्यजीवों द्वारा होने वाले फसलों के नुकसान को कम करने के लिये सौर ऊर्जा बाड़ की जगह अब बॉयो-फेंसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- बॉयो-फेंसिंग को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार की ओर से इसके लिये सेल गठित करने के साथ ही विशेष अधिकारी नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गए हैं। यह सेल बायो-फेंसिंग को बढ़ावा देने के साथ ही इन विषयों पर शोध भी करेगी।

नोट :

- कैंपा फंड में ही इसके लिये बजट की व्यवस्था की जाएगी। अलग-अलग फेंसिंग के लिये पौधों की प्रजाति का अध्ययन कराया जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि अब तक फसलों को नुकसान से बचाने के लिये सौर ऊर्जा बाड़ ही लगाई जाती थी, लेकिन इसे लगाने में खर्च अधिक आता है। विभाग की ओर से एक बार बाड़ लगाने के बाद इसे ग्रामीणों को सौंप दिया जाता है। ठीक से रखरखाव नहीं होने के कारण यह बाड़ जल्दी ही खराब हो जाती है और लाभार्थियों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते हैं।
- इस समस्या से बचने के लिये बीते दिनों मुख्य सचिव डॉ. सुखबीर सिंह संधु ने कैंपा (वनारोपण निधि प्रबंधन व योजना प्राधिकरण) संचालन समिति की बैठक में वनाधिकारियों को बॉयो-फेंसिंग बाड़ को बढ़ावा देने के निर्देश दिये थे।
- प्रदेश में खासतौर पर जंगली सूअर, हाथी और बंदर फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। जिस क्षेत्र में जिस वन्यजीव का आतंक अधिक है, उस क्षेत्र में उसी के अनुरूप बॉयो-फेंसिंग की जाएगी।
- मौसम, जलवायु और भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए अलग-अलग जगह पर अलग-अलग बॉयो-फेंसिंग की जाती है। इसमें आमतौर पर काला बाँस, कांटा बाँस, राम बाँस, जेरेनियम, लेमनग्रास, विभिन्न प्रकार के कैक्टस, यूफोरबिया एंटीकोरम (त्रिधारा), डेविल्स बैकबोन, पूर्वी लाल, क्लेरोडेंड्रम इनर्मिस, बोगनविलिया, करौंदा, जेट्रोफा करकस, डुरंटा इरेक्टा, हाईब्रिड विलेट्री, लीलैंड सरू और हेमेलिया आदि शामिल हैं।
- देहरादून वन प्रभाग के वनाधिकारी नीतीशमणि त्रिपाठी ने बताया कि बॉयो-फेंसिग का प्रयोग वर्ष 2015 में लैंसडाउन में किया गया था, जो सफल रहा। कुछ समय पहले रामनगर में भी यह तरीका अपनाया गया। इस प्रकार की फेंसिंग अनेक देशों में प्रयोग की जा रही है।
- इसके तहत मधुमक्खी पालन का बॉयो-फेंसिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें मधुमक्खी के डिब्बों को खेत के किनारे ज़मीन पर रखने के बजाय पेड़ों या खूंटों की मदद से ज़मीन से ऊपर एक तार की सहायता से लटका दिया जाता है। जैसे ही कोई जानवर इस तार को हिलाता है, मधुमिक्खयाँ बाहर आकर उस पर हमला कर देती हैं। हाथियों को खेतों से दूर रखने में यह तरीका कारगर साबित हुआ है।
- इसलिये बेहतर होती है बॉयो-फेंसिंग:
  - सौर ऊर्जा बाड़ से सस्ती पड़ती है तथा लगाने के बाद रखरखाव का बहुत ज्यादा झंझट नहीं।
  - विभिन्न प्रकार की बाड़ से विभिन्न प्रकार के उत्पादन भी मिलते हैं।
  - भूमि का कटाव रोकती हैं।
  - यह दीवार बनाने या गड्ढे खोदने से ज्यादा सस्ता सौदा है।

बाबा केदार के धाम में स्थापित होगा 60 क्विंटल वजनी काँसे का भव्य ऊँ

चर्चा में क्यों ?

16 मई, 2023 को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के ज़िलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि भगवान आशुतोष के द्वादश ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के गोल प्लाजा में 60 क्विंटल वजनी काँसे का भव्य ऊँ की आकृति स्थापित की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- ज़िलाधिकारी ने बताया कि ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग ने हाइड्रा मशीन की मदद से ऊँ आकृति को गोल प्लाजा में स्थापित करने के लिये ट्रायल किया, जो पूरी तरह से सफल रहा। जल्द ही इसे स्थायी रूप से स्थापित कर दिया जाएगा।
- विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ को सुरक्षित करने के साथ ही भव्य रूप से सँवारा जा रहा है। इन दिनों धाम में दूसरे चरण के कार्य जोरों पर चल रहे हैं। पहले चरण में मंदिर परिसर के विस्तार के साथ ही मंदिर मार्ग और गोल प्लाजा का निर्माण किया गया था।
- केदारनाथ स्थित गोल प्लाजा, जो मंदिर से लगभग ढाई सौ मीटर पहले संगम के ठीक ऊपर स्थित है, पर ऊँ की आकृति को स्थापित किया जा रहा है। केदारनाथ गोल प्लाजा में ऊँ की आकृति स्थापित होने से वहाँ की भव्यता और भी बढ़ जाएगी।
- 60 क्विंटल वजनी काँसे से ऊँ की आकृति को गुजरात के बड़ौदा में बनाया गया है।
- ऊँ की आकृति को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिये इसके चारों तरफ से तांबे से वेल्डिंग की जाएगी। साथ ही, मध्य हिस्से के साथ ही किनारों को भी सुरक्षित किया जाएगा, जिससे बर्फबारी से इसे नुकसान न हो। एक सप्ताह में ऊँ आकृति को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया जाएगा।

नोट :

राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को वापस लेगी सरकार

चर्चा में क्यों ?

16 मई, 2023 को उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य के पहले राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को 30 साल के लिये लीज पर देने के बाद सरकार अब इसे वापस लेगी। विभाग को इसके लिये सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिल गई है।

प्रमुख बिंदु

- विभाग के अधिकारियों के अनुसार कंपनी ने तय सेवा शर्तों को पूरा नहीं किया। यही वजह है कि स्टेडियम को वापस लिया जा रहा है।
- खेल विभाग के निदेशक जितेंद्र सोनकर के मुताबिक, वर्ष 2016-17 में करीब 253 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेडियम का निर्माण किया गया था। यह राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, जिसे कुछ शर्तों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को लीज पर दिया गया था।
- विदित है कि यह कंपनी देश की प्रमुख अवसंरचना विकास और वित्त कंपनी है। सरकारी क्षेत्र की इस कंपनी की 40 सहायक कंपनियाँ हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को लीज पर लेने के बाद कंपनी का दिवालिया निकल गया और उसने सेवा शर्तों को पूरा नहीं किया।
- कंपनी की ओर से एक ऐसा खाता खोला जाना था, जिसमें जमा धनराशि को बिना सहमति के निकाला नहीं जा सकता था, लेकिन खाता नहीं खोला गया। कंपनी को स्टेडियम परिसर में 2.8 एकड़ भूमि पर खेल अवस्थापनाओं के विकास के लिये दी गई थी, इसे भी पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज में आइस स्केटिंग रिंक को संचालित किया जाना था, इसे भी शुरू नहीं किया गया।
- साढ़े सात प्रतिशत ग्रॉस राजस्व पर दिये इस स्टेडियम को लेकर जो सेवा शर्तें थीं उसे पूरा न किये जाने से करोड़ों की लागत से बने इस स्टेडियम का ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्टेडियम को वापस लेने और इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की मंजूरी मिली है।
- गौरतलब है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देहरादून स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को वर्ष 2018 में होमग्राउंड के तौर पर अपनाया था। उस दौरान यहाँ कई टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए। इसके अलावा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने भी स्टेडियम को होमग्राउंड के रूप में चुना था।
- राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को वापस लेने के बाद इसे पीपीपी मोड में दिया जाएगा। संबंधित कंपनी से जो लेनदेन है उसे कैबिनेट में लाया जाएगा।

'पैच रिपोर्टिंग एप'

चर्चा में क्यों ?

18 मई, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कहीं से भी गड्ढायुक्त सड़क की फोटो खींचकर सरकार को भेजने के लिये एक 'पैच रिपोर्टिंग एप'का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों के गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत 'पैच रिपोर्टिंग एप'पर दर्ज करा सकेगा। उस सड़क की मरम्मत हो जाने के बाद शिकायतकर्त्ता को एप पर ही ठीक हुई सड़क की फोटो पूरी जानकारी के साथ भेज दी जाएगी।
- एप के माध्यम से प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने में काफी मदद मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि शिकायत मिलने के एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई के लिये अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए तथा उच्चाधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी करें।
- पैच रिपोर्टिंग एप में गड्ढे वाले स्थान की लोकेशन की सूचना स्वत: ही प्रदर्शित होगी। इसे प्रदेश में सड़कों को गड्ढामुक्त करने में सहयोग करने वाला यह मोबाइल एप लोक निर्माण विभाग की ओर से सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिये आमजन से परस्पर संवाद बनाए रखने के लिये विकसित किया गया है।

नोट :

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर

चर्चा में क्यों ?

18 मई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें एकल अभिभावकों को दो साल की चाइल्ड केयर लीव दिये जाने सहित कुल 16 प्रस्ताव पास हुए हैं।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में 'सीएम मेधावी छात्रवृत्ति योजना'पर भी मुहर लगाई गई, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- कक्षा 6 से कक्षा 10 तक छात्रवृत्ति परीक्षा के बाद अंकों के प्रतिशत के आधार पर छात्रवृत्ति मिलेगी। कक्षा 6 में 600 रुपए, कक्षा 7 में 700 रुपए, कक्षा 8 में 800 रुपए, कक्षा 9 में 900 रुपए, कक्षा 11 और 12 में 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति की राशि प्रतिमाह मिलेगी।
- कैबिनेट बैठक के अन्य महत्त्वपूर्ण फैसले :
  - कक्षा 6 से कक्षा 10 तक 70% से अधिक अंक होने चाहिये। परीक्षा में 75% अटेंडेंस ज़रूरी है।
  - उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में दो विषयों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा का मौका मिलेगा। फेल छात्रों के अलावा अपने अंकों में सुधार के लिये भी दी जा सकेगी परीक्षा।
  - प्रदेश में शहरों के हिसाब से अग्निशमन विभाग को 7 श्रेणियों में बाँटा गया है। प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग सुविधाएँ दी जाएंगी।
  - प्रदेश में 955 बीआरसी और सीआरसी 40000 रुपए प्रति माह वेतन पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रखे जाएंगे।
  - पर्यटन विभाग ने एयरोस्पोर्ट्स पैराग्लाइडिंग आदि के लिये नियमावली बनाई है, जिसके तहत शर्तें पूरी करके लाइसेंस लेना होगा, बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करवाने वालों पर 50000 रुपए तक जुर्माना लगेगा।
  - वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन पर मोहर, वाणिज्यकर को अब राज्य कर कहा जाएगा। आयुक्त कर को आयुक्त राज्य कर और मनोरंजन कर के 9 पद आरक्षित किये गए।
  - वित्तीय समिति के अधिकार बढ़ाए गए - अब एक करोड़ के बजाय 10 करोड़ तक के कार्यों को विभागीय सचिव के स्तर से बनी समिति से अप्रूवल मिल जाएगा। इससे ऊपर वालों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति से अप्रूवल मिलेगा।
  - भातखंडे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय की नियमावली पर मोहर।
  - प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये इको टूरिज्म स्थल पर होने वाली कमाई का केवल 10% हिस्सा ही ट्रेजरी में जमा होगा। 90% हिस्सा स्थानीय समिति के पास रहेगा जिससे वहाँ विकास कार्य किये जा सकेंगे। पुराने इको टूरिज्म स्थलों पर 20% हिस्सा ट्रेजरी में जमा होगा और 5 करोड़ से अधिक की रकम इकट्ठा होने और कोई नया काम संभावित न होने पर वह रकम ट्रेजरी में जमा हो जाएगी।
  - अब प्रदेश में एकल अभिभावकों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिल सकेगी। अभी तक केवल महिला कर्मचारी को यह सुविधा मिलती थी। अब एकल पुरुष अभिभावक को भी यह सुविधा मिलेगी। जिनके बच्चे 40% से अधिक दिव्यांग हैं उन्हें निर्धारित 18 साल के बाद भी सीसीएल का लाभ मिल सकेगा।
  - स्टोन क्रेशर हॉट मिक्स प्लांट के लिये बनी साइट सिलेक्शन कमेटी में अब हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक अधिकारी भी बतौर सदस्य होगा।
  - प्रदेश में निराश्रित गोवंश के लिये बनी गौशालाओं में अब प्रति गाय प्रतिदिन 30 रुपए के बजाय 80 रुपए का अनुदान सरकार देगी; इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर डीएम भी पैसा दे सकेंगे।
  - जमरानी बांध के विस्थापितों को उधम सिंह नगर के पराग फार्म में 300 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। इसकी विस्थापन नीति पूर्व में कैबिनेट से पास हो चुकी है।
  - नगर पंचायत कालाढूंगी का सीमा विस्तार किया जाएगा।
  - प्रदेश में नजूल नीति 2021 को 1 साल के लिये विस्तारित किया गया है।

नोट :

जमरानी बांध विस्थापित परिवारों के लिये 300 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

18 मई, 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के हल्द्वानी के रानीबाग क्षेत्र में बनने वाली जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के तहत विस्थापित होने वाले परिवारों के लिये 300 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- यह भूमि ऊधमसिंह नगर के पराग फार्म क्षेत्र में है, जहाँ विस्थापित परिवारों को बसाया जाएगा। राजस्व विभाग में दर्ज यह भूमि अब सिंचाई विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।
- विदित है कि जमरानी बांध परियोजना के तहत छह गाँवों के करीब 1323 परिवारों का पुनर्वास किया जाना है। इसके लिये राज्य सरकार पुनर्वास प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इसके तहत श्रेणी-एक के प्रति विस्थापित परिवार को एक एकड़ भूमि दी जाएगी।
- बांध निर्माण को लेकर अब तक करीब-करीब सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गई हैं। वित्तीय स्वीकृति भी हो गई है। बजट जारी होते ही बांध निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद आने वाले समय में हल्द्वानी समेत आस-पास के इलाकों के लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी।
- जमरानी बांध परियोजना को पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) की ओर से 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना'में शामिल किया गया है। इस परियोजना से न सिर्फ डेढ़ लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई युक्त पानी मिलेगा, बल्कि हल्द्वानी शहर की पेयजल आपूर्ति और 63 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन भी होगा।
- उल्लेखनीय है कि जमरानी बांध परियोजना के तहत इन दिनों पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन के लिये आपत्तियाँ मांगी गईं थीं, जिसे अप्रैल माह में प्रकाशित किया गया था।
- इसके बाद एडीएम प्रशासन नैनीताल के स्तर पर आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। सभी आपत्तियों पर सुनवाई के लिये अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद मुआवज़ा और ज़मीन बँटवारे आदि की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

स्थानीय समुदाय पर खर्च होगी ईको टूरिज्म की 90% कमाई

चर्चा में क्यों ?

18 मई, 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने ईको टूरिज्म गतिविधियों में रेवेन्यू शेयरिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत उत्तराखंड में ईको टूरिज्म से होने वाली आय का 90 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय स्तर पर खर्च किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत अब संरक्षित क्षेत्रों से बाहर वन क्षेत्रों में नए ईको टूरिज्म डेस्टिनेशंस में विभिन्न मदों (प्रवेश शुल्क, साहसिक गतिविधियों, पार्किंग, स्थगन सुविधाओं, कैंपिंग) में लिये जाने वाले शुल्क से होने वाली कमाई का पहले साल में 10 प्रतिशत और आगामी वर्षों में 20 प्रतिशत सरकार के खाते में जमा की जाएगी।
- पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिये स्थानीय स्तर पर गठित संस्थाएँ और समितियाँ इस पैसे का उपयोग पर्यटक स्थलों के रखरखाव व अन्य मदों में खर्च कर सकेंगी।
- यह व्यवस्था पहले वर्ष तक लागू रहेगी, जबकि दूसरे वर्ष से कमाई का 20 प्रतिशत हिस्सा सरकार और 80 प्रतिशत स्थानीय समुदाय को जाएगा।
- इसके अलावा ऐसे ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन, जिनकी आय जब एक समय के बाद पाँच करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी तब अतिरिक्त धनराशि राजकीय कोष में जमा की जाएगी। पहले से संचालित ईको टूरिज्म डेस्टिनेशंस के संबंध में 20 प्रतिशत राजकोष में जमा किया जाएगा, जबकि 80 प्रतिशत स्थानीय संस्थाओं के पास उनके रखरखाव आदि पर खर्च के लिये रहेगा।

नोट :

- ईको-टूरिज्म डेस्टिनेशंस को विकसित किये जाने पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले ज़िलों को तीन पुरस्कार भी दिये जाएंगे। प्रथम पुरस्कार के रूप में एक करोड़ रुपए, द्वितीय में 75 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50 लाख रुपए दिये जाएंगे।
- ज़िले इस पुरस्कार राशि का इस्तेमाल ईको-टूरिज्म की अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने में करेंगे। प्रथम स्थान पर आने वाले ज़िले पर अगले तीन वर्षों तक इस पुरस्कार के लिये विचार नहीं किया जाएगा।
- गौरतलब है कि प्रदेश में उत्तराखंड ईको टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वर्ष 2016 में की गई थी। इसके तहत अब रेवेन्यू शेयरिंग का प्रस्ताव पारित किया गया है।

प्रदेश को जल्द मिलेगी साइबर फॉरेंसिक लैब

चर्चा में क्यों ?

19 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार साइबर अपराधों में जाँच के लिये अब उत्तराखंड पुलिस को केंद्रीय फॉरेंसिक लैब या अन्य प्रदेशों की लैब पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जल्द ही प्रदेश को अपनी फॉरेंसिक लैब मिल जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार इसके लिये केंद्र सरकार द्वारा चार करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इसमें से सवा करोड़ रुपए बतौर लिमिट जारी भी कर दिये गए हैं।
- विदित है कि लगातार साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। वर्तमान में उत्तराखंड का देश में पाँचवां स्थान है, जहाँ सबसे ज्यादा साइबर अपराध दर्ज किये जाते हैं। बहुत से मामलों में कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य वस्तुओं को फॉरेंसिक जाँच के लिये केंद्रीय फॉरेंसिक लैब चंडीगढ़ भेजी जाती हैं।
- चंडीगढ़ लैब के ऊपर चंडीगढ़ पुलिस के मामलों की जाँच करने की प्राथमिकता रहती है। इसके बाद वह पंजाब और हरियाणा पुलिस को तरजीह देते हैं। ऐसे में उत्तराखंड या अन्य प्रदेशों की पुलिस का नंबर बहुत बाद में आता है।
- पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कई बार जाँच रिपोर्ट देरी से आने में मुकदमों की जाँच भी प्रभावित होती है। कोर्ट में जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी दबाव रहता है। ऐसे में पिछले साल साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित करने के लिये प्रस्ताव भेजा गया था।

अमर उजाला प्रथमा सम्मान

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2023 को अमर उजाला और देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित प्रथमा सम्मान समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने समाज को नई दिशा देने वाली 26 महिलाओं को प्रथमा 2023 सम्मान प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रथमा सम्मान पाने वाली इन महिलाओं में विश्वविद्यालय की कुलपति, एम्स की डायरेक्टर, प्रोफेसर, डॉक्टर, फिल्म अभिनेत्री, वैज्ञानिक, समाज सेवी, पर्यावरणविद्, खिलाड़ी, महिला उद्यमी से लेकर पहली महिला कैब ड्राइवर भी शामिल थीं।
- कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है। ये महिलाएँ न केवल समाज को अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं, बल्कि हज़ारों-लाखों बेटियों के लिये प्रेरणा भी बन रही हैं।
- इस दौरान महिला बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल, कैब ड्राइवर इमराना, अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नीरजा गोयल को भी सम्मानित किया गया।
- कार्यक्रम का आयोजन आरबीएस डेवलपर, निलाया हाइट्स व निलाया हिल्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्रीट मिल्क रस्क व नमकीन के सहयोग से किया गया।

नोट :

पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड और गोवा बनेंगे सहयोगी

चर्चा में क्यों ?

23 मई, 2023 को पर्यटन के विभिन्न आयामों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- समझौता ज्ञापन पर उत्तराखंड पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे तथा गोवा के पर्यटन निदेशक सुनील अचिंपका द्वारा हस्ताक्षर किये गए।
- दोनों राज्य पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से संयुक्त कार्य योजना के आधार पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने तथा पर्यटन सुविधाओं के विकास में दोनों राज्यों के मध्य यात्रा सुविधाओं को बेहतर बनाने के भी प्रयास करेंगे।
- समझौता ज्ञापन के तहत पर्यटकों की सुविधा के लिये गोवा से उत्तराखंड के लिये एक से अधिक सीधी उड़ान कनेक्टिविटी सुविधा पर ध्यान देने, गोवा एवं उत्तराखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत से पर्यटकों को परिचित कराने के लिये सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों, रोड शो, आपसी पर्वों का आयोजन, स्थानीय व्यंजनों, लोक संस्कृति हस्त शिल्पों को प्रदर्शित करने के अवसर पैदा करने के प्रयास किये जाएंगे।
- विभिन्न पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये संयुक्त पैकेजों के अन्वेषण पर दोनों पक्ष पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे। दोनों राज्य पर्यटन के क्षेत्र की बेस्ट प्रेक्टिस को भी साझा करेंगे।
- साहसिक पर्यटन गतिविधियों में दोनों राज्य प्रमुख साहसिक गतिविधियों जैसे वाटर स्पोर्ट्स एयरो स्पोर्ट्स और भूमि आधारित गतिविधियों को संयुक्त रूप से बढ़ावा देंगे। साहसिक पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने के लिये राज्यों द्वारा निजी क्षेत्र एवं युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया जाएगा।

नोट :

- पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, हॉट एयर बैलून, स्कीइंग आदि भूमि आधारित गतिविधियाँ, माउंटेन बाइकिंग ट्रेकिंग/हाइकिंग, सभी टेरेना मोटर बाइकिंग, बजी गाडेस्टिनेशन जैसे टिहरी नैनीताल बौर जला उत्तराखंड में नानकमत्ता और अन्य जल निकाय क्षेत्रों में संभावनाएँ तलासी जाएंगी।
- इन गतिविधियों में एयरो स्पोर्ट्स पावर्ड हैंग ग्लाइडर, वाटर स्पोर्ट्स पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, जेट बोट्सवर, जेट्स वॉट्स, फ्लाई बोर्डिंग, वॉटर गोवा के जल क्रीड़ा के साथ-साथ जल क्रीड़ाओं के लिये संयुक्त रूप से विकसित और प्रचारित किये जाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- इको टूरिज्म के क्षेत्र में दोनों राज्यों में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव हैं। अभयारण्य जिन्हें इकोटूरिज्म के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। दोनों राज्य आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और विकसित करने रणनीति के लिये संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं।
- वेलनेस टूरिज्म के क्षेत्र में उत्तराखंड में आयुर्वेदिक और योग के क्षेत्र में बडी संभावनाएँ हैं, जबकि गोवा में कई स्पा और वेलनेस रिसॉर्ट हैं जिन्हें संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है।
- इसी प्रकार विरासत पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड और गोवा दोनों का औपनिवेशिक इतिहास है और वहाँ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कई स्थान हैं, जिसके लिये संयुक्त प्रचार रणनीति के तहत काम किया जा सकता है।
- मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में दोनों पक्ष मिलकर काम करेंगे और पर्यटन के क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान सुनिश्चित करने की दिशा में भी सहयोगी बनेंगे।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह पहल अन्य राज्यों को भी प्रेरित करेगी। गोवा से देहरादून की पहली सीधी उड़ान सेवा का लाभ दोनों राज्यों के नागरिक उठा सकेंगे, जिससे दोनों राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- गोवा तथा देहरादून के बीच यह सीधी उड़ान दोनों राज्यों के लोगों को यात्रा के लिये प्रेरित करेगी, सागर से हिमालय के दर्शन का अवसर पर्यटकों को मिलेगा।
- इस एमओयू से दोनों राज्यों के पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ एक-दूसरे राज्यों को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड तथा गोवा दोनों ही पर्यटन प्रधान छोटे राज्य हैं। दोनों राज्य आपसी समन्वय से इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं तथा समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं।
- गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे ने भी गोवा एवं उत्तराखंड बीच हुए एमओयू को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों राज्यों के पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। गोवा की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन है। गोवा में 35% से अधिक रोज़गार पर्यटन से पैदा होते हैं।
- गोवा सरकार ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के विजन पर कार्य कर रही है। राज्य आपसी समन्वय के साथ अपने क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। वर्तमान में गोवा सन, सेंड एवं सी के सिद्धांत से भी आगे बढ़ गया है। यहाँ साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म, आध्यात्म पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर कार्य हो रहे हैं।

दून जू में शुरू होगी टाइगर सफारी

चर्चा मे क्यों ?

23 मई, 2023 को उत्तराखंड के देहरादून चिड़ियाघर के वन क्षेत्राधिकारी मोहन सिंह रावत ने बताया कि राज्य के विश्व प्रसिद्ध जिम कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व की तर्ज पर शीघ्र ही देहरादून जू में भी टाइगर सफारी शुरू हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- यहाँ टाइगर सफारी के लिये ट्रैक तैयार हो चुका है, जबकि 11 बाड़ों (इनक्लोजर) बनाने का काम अंतिम चरण में है। बाड़ों का काम पूरा होते ही नैनीताल जू से बाघों के एक जोड़े को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद सैलानी जू क्षेत्र के कुल 25 हेक्टेयर हिस्से का दीदार कर सकेंगे।
- विदित है कि अभी तक जू की गतिविधियाँ मात्र पाँच हेक्टेयर क्षेत्रफल में संचालित की जा रही हैं।
- देहरादून चिड़ियाघर में टाइगर सफारी शुरू करने के लिये सेंट्रल जू अर्थारिटी (सीजेडए) की टीम भी दौरा कर चुकी है। बाड़ों का काम पूरा होते ही एक बार फिर सीजेडए की टीम मौका मुआयना करने के बाद अनुमति प्रदान करेगी।

नोट :

- टाइगर सफारी के लिये तैयार इस ट्रैक में जिप्सी के बजाए इलेक्ट्रिक वाहनों से सैलानियों को घुमाया जाएगा, ताकि वाहनों के शोर और प्रदूषण से बचा जा सके।
- ज्ञातव्य है कि इस चिड़ियाघर की शुरूआत वर्ष 1976 में वन चेतना केंद्र के रूप में की गई थी। मालसी गाँव में होने और हिरन की संख्या अधिक होने के कारण बाद में इसका नाम मालसी डियर पार्क पड़ गया। मार्च 2012 में इसे मिनी जू में तब्दील कर दिया गया। अब यहाँ टाइगर सफारी शुरू होने के बाद जू को नई पहचान मिलने जा रही है।
- दून चिड़ियाघर में एक माह में गुलदार के दो शावकों को चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर से यहाँ लाया जाएगा। इसके अलावा दो भालू (स्लोथ और ब्लैक बीयर प्रजाति), दो लोमड़ी, दो हाइना (लकड़बग्घा) को भी जू में लाया जाएगा।
- गौरतलब है कि वर्तमान में जू में एक मादा गुलदार, 23 प्रकार की प्रजातियों की चिड़िया, 23 प्रकार के वन्यजीव, साँपों की दस प्रजातियाँ, मगरमच्छ, घड़ियाल जैसे जीव मौजूद हैं। इसके अलावा मछलियों के लिये एक्वेरियम तैयार किया गया है।
- देहरादून जू हमेशा से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। बीते वर्ष 2022 में चिड़ियाघर में सात लाख 65 हज़ार पर्यटक आए। यहाँ प्रतिदिन 12 से 15 सौ पर्यटक पहुँचते हैं, जबकि रविवार को पर्यटकों की संख्या चार से पाँच हज़ार तक पहुँच जाती है। चिड़ियाघर को करीब तीन करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई हुई। इसी पैसे से वन्यजीवों की देखभाल, खाना और अन्य खर्च किये जाते हैं।
- जू में माँसाहारी वन्यजीवों को मंगलवार के दिन उपवास रखा जाता है। इस दिन उन्हें किसी प्रकार का भोजन नहीं दिया जाता है। ऐसा उनके संतुलित आहार के मद्देनजर किया जाता है।

प्रधानमंत्री ने देहरादून से दिल्ली के बीच 'वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन'की पहली यात्रा का शुभारंभ झंडी दिखाकर किया

चर्चा में क्यों ?

25 मई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन झंडी दिखाकर किया। उन्होंने नव विद्युतीकृत रेल खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित किया और उत्तराखंड को 100 प्रतिशत विद्युत कर्षण (ट्रैक्शन) वाला राज्य घोषित किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- यह उत्तराखंड में प्रारंभ होने वाली पहली 'वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन' है। यह ट्रेन देश की राजधानी को उत्तराखंड की देवभूमि से जोड़ेगी। दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय और कम हो जाएगा और ट्रेन में उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाएँ एक सुखद यात्रा का अनुभव कराएंगी।
- ट्रेन स्वदेशी है और कवच तकनीक सहित उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से दिल्ली के बीच की दूरी 4.5 घंटे में तय करेगी।
- प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विकास के 9 रत्नों का जिक्र किया-
  - पहला - केदारनाथ-बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपए के जीर्णोद्धार का काम।
  - दूसरा - गौरीकुंड-केदारनाथ और गोबिंद घाट-हेमकुंड साहिब में 2500 करोड़ रुपए की रोपवे परियोजना।
  - तीसरा - मानस खंड मंदिर माला कार्यक्रम के अंतर्गत कुमाऊँ के प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार।
  - चौथा - पूरे राज्य में होमस्टे का प्रचार (राज्य में 4000 से अधिक होमस्टे पंजीकृत हैं)।
  - पाँचवाँ - 16 इकोटूरिज़्म स्थानों का विकास।
  - छठा - उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (ऊधमसिंह नगर में एम्स का उप केंद्र)।
  - सातवाँ - 2000 करोड़ रुपए की टिहरी झील विकास परियोजना।
  - आठवाँ - हरिद्वार ऋषिकेश को योग और साहसिक पर्यटन की राजधानी के रूप में विकसित करना।
  - नवां - टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन।
- उन्होंने बताया कि 12,000 करोड़ रुपए की लागत से चार धाम महापरियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे यात्रा को तेज और आसान बना देगा।
- उन्होंने कहा कि 16,000 करोड़ रुपए की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना 2-3 वर्षों में पूरी हो जाएगी। यह परियोजना उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से को सुलभ बनाएगी और निवेश, उद्योग और रोज़गार को बढ़ावा देगी।

गंगोत्री में 5जी की दो लाखवीं साइट लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

24 मई, 2023 को केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में 5जी की दो लाखवीं साइट की लांचिंग डिजिटल बटन दबाकर देहरादून से की। इसके साथ ही चारों धाम अब 5जी सेवा से जुड़ गए हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- अब चारों धामों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हो गई है। इससे जहाँ चारधाम मंदिर परिसरों के आस पास श्रद्धालुओं को इंटरनेट की बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, वहीं आपदा प्रबंधन, सर्विलांस और रियल टाइम आधार पर यात्रा की निगरानी रखने में भी मदद मिलेगी।
- केंद्रीय संचार मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड के 1581 सीमांत व वाइब्रेंट गाँवों में 4जी सेवाएँ दी जाएंगी। 'वाइब्रेंट विलेज योजना' के तहत केंद्र सरकार ने ऐसे 2800 गाँवों के लिये धनराशि की व्यवस्था कर दी है। ये सारी जिम्मेदारी बीएसएनएल को दी गई है।
- विदित है कि 4जी व 5जी कनेक्टिविटी की योजना पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। देश के प्रत्येक पंचायत, ब्लाक, तहसील और ज़िला मुख्यालय में ये तकनीक उपलब्ध होगी। यह सुविधा तकरीबन सभी ज़िला मुख्यालयों तक पहुँच गई है।
- ज्ञातव्य है कि देश अब टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्टर बन रहा है। यहाँ के इंजीनियरों ने 6जी पेटेंट कराने शुरू कर दिये हैं। ऐसे 100 से अधिक पेटेंट हो चुके हैं।

उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2023 को मिली मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

25 मई, 2023 को उत्तराखंड शासनादेश सचिव बृजेश कुमार संत ने बताया कि शासन ने राज्य संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- इससे प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही संस्थाओं की प्रशासनिक योजनाओं का अनुमोदन भी आसानी से किया जा सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि इस संबंध में वर्ष 2021 में कैबिनेट की बैठक में मामला आया था, जिस पर मंत्रिमंडल ने विचार करने के बाद निर्णय लेने के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया था।
- उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2023 के लागू हो जाने के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करते हुए नियुक्ति की जा सकेंगी।

नोट :

वाइब्रेंट विलेज के निवासियों को दो घर देने की तैयारी

चर्चा में क्यों ?

28 मई, 2023 को उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की नोडल अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि प्रदेश के चार वाइब्रेंट विलेज के निवासियों को सीजनल माइग्रेशन वाले स्थानों पर भी राज्य सरकार घर बनाकर देने की तैयारी कर रही है। इसके लिये हाल ही में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गए।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश मिले हैं कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत हर गाँव की विशेषता को देखते हुए तीन माह के भीतर एक्शन प्लान तैयार किया जाए।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रदेश के चार सीमांत गाँव नीति, माणा, मलारी और गूंजी शामिल हैं।
- वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत हर गाँव के ऐसे परिवारों को दोनों स्थानों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास दिया जाएगा। इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी।
- वहीं, ये भी तय हुआ है कि ज़िलों में ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की जनपद स्तरीय समिति और फिर खंड स्तरीय समिति गठित होगी।
- वाइब्रेंट विलेज में रहने वाले लोगों से फल, सब्जियाँ, दूध, अंडे, मीट आदि सामग्री को सीमा सुरक्षा बल खरीदेंगे। इसके लिये भी एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही हाई पावर कमेटी को भेजा जाएगा।
- अगर किसी गाँव का सेना या सुरक्षा बलों के साथ कोई समस्या या मुद्दा है तो इसका प्रस्ताव भी शासन को भेजना होगा। हर वाइब्रेंट विलेज में एक ग्रोथ सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। आईटीबीपी ने भी सभी वाइब्रेंट विलेज के लिये अपना एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
- मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने निर्देश दिये हैं कि जिन वाइब्रेंट विलेज में सार्वजनिक परिवहन की समस्या है, वहाँ मिनी बस का संचालन किया जाएगा। इसके लिये संबंधित ज़िले से प्रस्ताव परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
- भूमि अधिकारों से संबंधित समस्याओं का सभी ज़िले राजस्व विभाग के साथ समन्वय बनाकर तत्काल समाधान करेंगे। वाइब्रेंट विलेज में टेली मेडिसिन की सुविधा भी दी जाएगी।

मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण निधि (कॉर्प्स फंड)

चर्चा में क्यों ?

26 मई, 2023 को उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने बताया कि प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिये विभाग ने मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण और मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण निधि (कॉर्प्स फंड) को हरी झंडी दे दी है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष में प्रतिवर्ष 60 से 70 लोगों की मौत हो जाती है तथा ढ़ाई से तीन सौ लोग घायल हो जाते हैं। ऐसी घटनाओं में तत्काल राहत पहुँचाने के लिये राज्य सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ के साथ ही दो करोड़ रुपए के कॉर्प्स फंड की स्थापना की है।
- इस धनराशि में राज्य सरकार अपने विवेक से कमी एवं वृद्धि भी कर सकेगी। खास बात यह है कि धनराशि नॉन लेप्सेबल होगी। यानि हर साल जितना भी फंड बचेगा, वह आगे भी बना रहेगा और आगे जो राशि प्राप्त होगी, फंड में जुड़ती चली जाएगी।
- प्रकोष्ठ में वन विभाग के एक वन क्षेत्राधिकारी, अनुबंध के आधार पर एक जीआईएस विशेषज्ञ और दो जेआरएफ, एसआरएफ विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाएगी।

नोट :

- मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव (चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन) के कार्यालय के तहत संचालित होगा। प्रकोष्ठ की स्थापना राज्य में मानव एवं वन्यजीवों के मध्य होने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किये जाने के लिये की गई है।
- क्या काम करेगा प्रकोष्ठ:
  - प्रदेश में होने वाली प्रत्येक मानव-वन्यजीव घटना का डाटा इकट्ठा करना।
  - घटना के बाद अनुग्रह राशि के भुगतान की स्थिति में अनुश्रवण करना।
  - सभी घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण।
  - अन्य देशों और प्रदेशों में इस विषय में उठाए जा रहे कदमों का अध्ययन।
  - प्रदेश में वन्यजीवों की गणना में भागीदारी।
  - अन्य तकनीकी कार्य।

प्रदेश की 1114 गाँवों में फाइबर टू होम कनेक्शन से फ्री वाईफाई

चर्चा में क्यों ?

29 मई, 2023 को उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि प्रदेश की 1114 ग्राम पंचायतों के सभी सरकारी कार्यालयों, निकायों में जल्द ही फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। इसके लिये सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) और बीएसएनएल के बीच करार हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- आईटीडीए की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि 50 करोड़ की इस परियोजना के लिये बीएसएनएल के साथ करार किया गया है।
- इसके तहत 3090 फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन दिये जाएंगे। साथ ही, अगले पाँच सालों तक इनकी देखरेख भी बीएसएनएल ही सँभालेगा।
- गौरतलब है कि पिछले साल एफटीटीएच योजना के लिये सरकार ने 50 करोड़ का बजट जारी किया था, लेकिन समय से काम शुरू नहीं हो पाया। 31 मार्च के बाद बजट लैप्स होने से बचाने के लिये सरकार ने इस साल दोबारा यह बजट दिया है।
- इस योजना के तहत बीएसएनएल प्रदेश की 1114 ग्राम पंचायतों में एफटीटीएस सेवा देगा। इसके दायरे में उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी संस्थानों से लेकर पंचायत घर तक शामिल होंगे। इन सभी जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी।
- विदित हो कि भारत नेट-1 के तहत जिन ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम बीएसएनएल को दिया गया था, उसे तय समय में वह पूरा नहीं कर पाया था।

नोट :